Original Research Article Website : www.ijbasr.org IF = 5.1 ISSN : 2349-1965
International Journal of Basic & Applied Science Research
Multidiscipline and Peer Reviewed Refereed Journal 2026; 13(3); 14-20 (Special Issue)

महिला सशक्तिकरण में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की भूमिका : दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंड के संदर्भ में

वीर कुमार
बिठौली, बहेरी, दरभंगा (बिहार)

सार

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार की एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किया गया, जिससे पारंपरिक ईंधनों जैसे लकड़ी, उपले एवं कोयले पर निर्भरता कम हुई। प्रस्तुत शोध पत्र दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंड में महिला सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रभाव का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन में 120 महिला लाभार्थियों का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति द्वारा किया गया। शोध में पाया गया कि योजना ने महिलाओं के स्वास्थ्य, समय प्रबंधन, सामाजिक सम्मान एवं निर्णय लेने की क्षमता में सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न किया है। हालांकि, गैस सिलेंडर की पुनः भराई की उच्च लागत तथा आर्थिक सीमाएँ योजना के पूर्ण उपयोग में बाधा उत्पन्न करती हैं। अध्ययन यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर एवं सशक्तिकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मुख्य–शब्दः महिला सशक्तिकरण; प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना; ग्रामीण समाज; स्वच्छ ईंधन।

परिचय

भारत एक कृषि प्रधान एवं ग्रामीण बहुल देश है, जहाँ आज भी बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन पकाने के लिए लकड़ी, उपले, फसल अवशेष तथा कोयले जैसे पारंपरिक ईंधनों का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता रहा है। इन ईंधनों से उत्पन्न धुआँ महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव डालता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार घरेलू वायु प्रदूषण श्वसन रोग, आँखों की जलन, अस्थमा तथा फेफड़ों से संबंधित अनेक गंभीर बीमारियों का प्रमुख कारण है (WHO, 2022)। ग्रामीण परिवारों में महिलाएँ भोजन बनाने की मुख्य जिम्मेदारी निभाती हैं, इसलिए वे इस प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। (WHO, 2022)

भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका केवल घरेलू कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे परिवार की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना की आधार शिला भी हैं। इसके बावजूद ग्रामीण महिलाओं को लंबे समय तक ऊर्जा संसाधनों की कमी, स्वास्थ्य समस्याओं तथा सामाजिक असमानताओं का सामना करना पड़ा है। ईंधन संग्रह करने में महिलाओं का अत्यधिक समय एवं

Corresponding Author : वीर कुमार
E-mail : veerkumar.viru@gmail.com
Date of Acceptance : 29.01.2026
Date of Publication : 01.05. 2026

श्रम व्यय होता था, जिससे उनके शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक भागीदारी के अवसर सीमित हो जाते थे (शर्मा एवं सिंह, 2021)। ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं को स्वच्छ एवं सुरक्षित ऊर्जा उपलब्ध कराना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना गया।

इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार ने मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना था। योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन महिलाओं के नाम पर जारी किए गए, जिससे महिलाओं की सामाजिक पहचान एवं सम्मान को भी बढ़ावा मिला (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, 2025)। योजना का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराकर महिलाओं को धुएँ से मुक्ति दिलाना तथा उनके स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर में सुधार लाना था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार की उन प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिसने महिला सशक्तिकरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। योजना के माध्यम से महिलाओं को पारंपरिक चूल्हों के धुएँ से राहत मिली तथा भोजन पकाने की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनी। इससे महिलाओं के श्रम एवं समय की बचत हुई, जिसे वे शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा आय वर्धक गतिविधियों में उपयोग कर सकती हैं (कुमारी एट अल., 2026)। इसके अतिरिक्त योजना ने महिलाओं के आत्मविश्वास एवं निर्णय क्षमता को भी प्रभावित किया है, क्योंकि गैस कनेक्शन उनके नाम पर जारी किए जाते हैं।

ग्रामीण समाजशास्त्र के संदर्भ में देखा जाए तो ऊर्जा संसाधनों तक पहुँच सामाजिक परिवर्तन का एक महत्त्वपूर्ण सूचक है। जब महिलाओं को सुरक्षित एवं आधुनिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध होते हैं, तब उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। इससे परिवार के भीतर उनकी स्थिति मजबूत होती है तथा सामाजिक सम्मान में वृद्धि होती है (बेहरा एवं मल्लिक, 2023)। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने ग्रामीण महिलाओं को केवल ऊर्जा सुविधा ही नहीं दी, बल्कि उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर भी प्रदान किया है।

बिहार जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में इस योजना का विशेष महत्त्व है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बड़ी संख्या में परिवार पारंपरिक ईंधनों पर निर्भर हैं। दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंड में भी अधिकांश ग्रामीण परिवार कृषि एवं दिहाड़ी मजदूरी पर आधारित जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ महिलाओं को ईंधन संग्रह के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जिससे उनके समय एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लागू होने के बाद महिलाओं के जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। महिलाओं को अब धुएँ से मुक्ति मिली है, खाना पकाने में कम समय लगता है तथा घरेलू वातावरण अधिक स्वच्छ एवं सुरक्षित बना है (ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 2025)।

हालाँकि योजना के सकारात्मक प्रभावों के बावजूद कुछ व्यावहारिक समस्याएँ भी सामने आई हैं। एलपीजी सिलेंडर की पुनः भराई की बढ़ती कीमतें गरीब परिवारों के लिए आर्थिक बोझ बनती जा रही हैं। कई परिवार गैस कनेक्शन होने के बावजूद नियमित रूप से सिलेंडर रिफिल नहीं करा पाते और पुनः पारंपरिक ईंधनों का

उपयोग करने लगते हैं (अशरफ एवं टोल, 2024)। इससे योजना के स्थायी उपयोग में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केवल एक ऊर्जा योजना नहीं है, बल्कि यह महिला स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, सामाजिक सम्मान एवं जीवन स्तर में सुधार से जुड़ी व्यापक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह योजना महिलाओं को घरेलू कार्यों तक सीमित रखने वाली पारंपरिक संरचनाओं को चुनौती देती है तथा उन्हें अधिक आत्मनिर्भर एवं जागरूक बनाती है। इसलिए यह आवयक है कि योजना के सामाजिक प्रभावों का स्थानीय स्तर पर गहन अध्ययन किया जाए।

इसी संदर्भ में प्रस्तुत शोध पत्र दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंड में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की भूमिका का समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करता है।

साहित्य समीक्षा :

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर विभिन्न शोधकर्ताओं एवं संस्थाओं द्वारा किए गए अध्ययनों में इसके सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। अधिकांश अध्ययनों में यह पाया गया कि योजना ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाया है, हालांकि कुछ आर्थिक एवं संरचनात्मक चुनौतियाँ अब भी विद्यमान हैं।

बेहरा एवं मल्लिक (2023) ने बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया। उनके अध्ययन में यह पाया गया कि योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध हुआ, जिससे घरेलू वायु प्रदूषण में कमी आई। अध्ययन में यह भी स्पष्ट किया गया कि एलपीजी सिलेंडर की पुनः भराई की लागत गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। कई परिवार प्रारंभिक गैस कनेक्शन प्राप्त करने के बाद नियमित रूप से गैस का उपयोग नहीं कर सके। शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि सरकार को रिफिल सब्सिडी को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए ताकि योजना का सतत उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। कुमारी एट अल (2026) ने ग्रामीण महिलाओं में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कारण उत्पन्न व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया। शोध में पाया गया कि योजना ने महिलाओं की जीवन शैली में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए। महिलाओं ने पारंपरिक चूल्हों के धुएँ से राहत मिलने के कारण स्वास्थ्य में सुधार का अनुभव किया। अध्ययन के अनुसार महिलाएँ अब भोजन बनाने में कम समय व्यतीत करती हैं तथा उनके दैनिक श्रम में कमी आई है। शोधकर्ताओं ने यह भी उल्लेख किया कि योजना ने महिलाओं में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायता की।

अशरफ एवं टोल (2024) ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावों का विश्लेषण किया। उनके अध्ययन में यह निष्कर्ष निकला कि योजना ने एलपीजी उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि की तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा के प्रसार को बढ़ावा दिया। अध्ययन में अनुसूचित जाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को योजना से अधिक लाभ प्राप्त होने की बात कही गई। हालांकि, शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि गरीब परिवारों में एलपीजी के नियमित उपयोग में आर्थिक सीमाएँ प्रमुख बाधा हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि योजना की दीर्घकालिक सफलता हेतु एलपीजी रिफिल पर अतिरिक्त आर्थिक सहायता आवश्यक है।

इंटरनेशनल इनर्जी एजेंसी (2023) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि योजना के कारण करोड़ों महिलाओं को सुरक्षित एवं स्वच्छ खाना पकाने की सुविधा प्राप्त हुई। इससे महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य जोखिमों में कमी आई तथा पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में भी सकारात्मक परिवर्तन देखा गया।

इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (2025) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार की सबसे प्रभावी सामाजिक योजनाओं में से एक है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि योजना ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार, घरेलू स्वच्छता में वृद्धि तथा समय की बचत में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त योजना ने महिलाओं के सम्मान एवं आत्मविश्वास को भी बढ़ाया है।

शर्मा एवं सिंह (2021) ने उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य पर पारंपरिक ईंधनों के प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि लकड़ी एवं उपलों के धुएँ के कारण महिलाओं में श्वसन रोग, आँखों की जलन तथा फेफड़ों से संबंधित समस्याएँ अधिक पाई जाती हैं। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि स्वच्छ ईंधन योजनाएँ महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण में अत्यंत उपयोगी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम बताया।.

कुमार एवं तिवारी (2024) ने बिहार के रोहतास जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रति लाभार्थियों की धारणा एवं चुनौतियों का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश महिलाओं ने योजना के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया। महिलाओं ने बताया कि गैस उपयोग से खाना जल्दी बनता है तथा धुएँ से होने वाली समस्याएँ कम हुई हैं। हालांकि अध्ययन में आर्थिक कठिनाइयों, गैस एजेंसी की दूरी तथा समय पर सिलेंडर उपलब्ध न होने जैसी समस्याओं को भी रेखांकित किया गया।.

ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (2025) की सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने "स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन" के लक्ष्य को ग्रामीण भारत में साकार करने का प्रयास किया है। रिपोर्ट के अनुसार योजना ने महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार के साथ–साथ उन्हें सामाजिक गरिमा एवं आत्मनिर्भरता प्रदान की है। सरकार द्वारा महिलाओं के नाम पर गैस कनेक्शन जारी करने से परिवार के भीतर उनकी पहचान एवं निर्णय क्षमता को मजबूती मिली है।

उपरोक्त साहित्य समीक्षा से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति एवं जीवन स्तर में सुधार लाने वाली महत्त्वपूर्ण योजना सिद्ध हुई है। अधिकांश अध्ययनों में योजना के सकारात्मक प्रभावों को स्वीकार किया गया है, किन्तु आर्थिक समस्याएँ, रिफिल की उच्च लागत तथा जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियाँ इसके पूर्ण उपयोग में बाधा उत्पन्न करती हैं। प्रस्तुत अध्ययन दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंड के संदर्भ में इन सामाजिक एवं व्यावहारिक पहलुओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करने का प्रयास करता है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. बेनीपुर प्रखंड की महिलाओं पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करना।
2. महिलाओं के स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करना।
3. योजना के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं एवं चुनौतियों का अध्ययन करना।

अनुसंधान पद्धति :

प्रस्तुत अध्ययन समाजशास्त्रीय शोध पद्धति पर आधारित है। अध्ययन का क्षेत्र बिहार राज्य के दरभंगा जिला अंतर्गत बेनीपुर प्रखंड को चुना गया। अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया। प्राथमिक आँकड़ों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची एवं प्रत्यक्ष अवलोकन पद्धति द्वारा किया गया। अध्ययन हेतु 120 महिला लाभार्थियों का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति के माध्यम से किया गया। चयनित उत्तरदाताओं में विभिन्न जाति एवं आर्थिक वर्गों की महिलाएँ सम्मिलित थीं। द्वितीयक आँकड़े सरकारी रिपोर्टों, शोध पत्रों, पुस्तकों, समाचार पत्रों एवं ऑनलाइन स्रोतों से संकलित किए गए। यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेशणात्मक प्रकृति का है। प्राप्त आँकड़ों का प्रतिशत पद्धति द्वारा विश्लेषण किया गया।

तालिकाः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से महिलाओं को प्राप्त प्रमुख लाभ

क्र. सं.	लाभ का प्रकार	उत्तरदाताओं की संख्य	प्रतिशत
1	स्वास्थ्य में सुधार	30	31.67:
2	समय की बचत	27	22.50:
3	धुएँ से मुक्ति	24	20.00:
4	सामाजिक सम्मान में वृद्धि	18	15.00:
5	निर्णय क्षमता में वृद्धि	13	10.83:
6	कुल	120	100.00

विश्लेषण :

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 31.67 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि योजना के कारण उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। पारंपरिक चूल्हे के धुएँ से होने वाली आँख एवं श्वसन संबंधी समस्याओं में कमी आई है। 22.50 प्रतिशत महिलाओं ने समय की बचत को योजना का प्रमुख लाभ बताया। पहले महिलाओं को लकड़ी एवं अन्य ईंधनों के संग्रह में काफी समय लगाना पड़ता था, जबकि एलपीजी के उपयोग से यह समस्या कम हुई है।

20 प्रतिशत महिलाओं ने धुएँ से मुक्ति को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन माना। इससे घरेलू वातावरण अधिक स्वच्छ एवं सुरक्षित बना है। 15 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि गैस कनेक्शन उनके नाम पर होने से परिवार एवं समाज में उनका सम्मान बढ़ा है। 10.83 प्रतिशत महिलाओं ने घरेलू निर्णयों में अपनी भागीदारी बढ़ने की बात कही।

हालाँकि कुछ महिलाओं ने यह भी बताया कि गैस सिलेंडर की कीमत अधिक होने के कारण वे नियमित रिफिल नहीं करा पाती हैं। इसलिए कई परिवार एलपीजी एवं पारंपरिक ईंधनों दोनों का मिश्रित उपयोग करते हैं।

चर्चा :

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बहुआयामी परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। योजना ने महिलाओं को स्वास्थ्य सुरक्षा, समय की बचत एवं स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराया है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है तथा वे अधिक आत्मविश्वास के साथ घरेलू निर्णयों में भाग लेने लगी हैं।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह योजना केवल ऊर्जा उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण कदम है। योजना ने महिलाओं के श्रम भार को कम किया तथा उन्हें सामाजिक गरिमा प्रदान की है। फिर भी योजना की स्थायी सफलता हेतु आवश्यक है कि सरकार सिलेंडर रिफिल की लागत को कम करे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी की उपलब्धता को और सुलभ बनाए। आर्थिक सहायता एवं जागरूकता कार्यक्रम योजना के प्रभाव को और अधिक व्यापक बना सकते हैं।

निष्कर्ष :

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ग्रामीण महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने वाली एक महत्त्वपूर्ण योजना सिद्ध हुई है। दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंड में किए गए अध्ययन से स्पष्ट होता है कि योजना ने महिलाओं के स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति एवं जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार किया है। महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होने से धुएँ से मुक्ति मिली तथा समय एवं श्रम की बचत हुई। योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी पहल है, किन्तु इसकी स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए सिलेंडर रिफिल की लागत को कम करना तथा आर्थिक सहायता बढ़ाना आवश्यक है। यदि सरकार एवं समाज मिलकर योजना के क्रियान्वयन को मजबूत करें, तो यह ग्रामीण महिलाओं के समग्र विकास में और अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती है।

संदर्भ :

1. अशरफ, एन., और टोल, आर. एस. जे. (2024). भारतीय परिवारों पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रभाव, अजंता प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 61
2. बेहेरा, बी., और मलिक, बी. (2023). प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन और अपनाने में डीलरों और परिवारों द्वारा महसूस की गई बाधाएँ. Indian Journal of Extension Education, 59(3), 31–35.
3. Indian Brand Equity Foundation. (2025). प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. IBEF- पृ. 44
4. International Energy Agency- (2023)- India energy outlook 2023- International Energy पृ. 82
5. कुमार, डी., और तिवारी, ए. (2024). बिहार के रोहतास जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को अपनाने में महसूस की गई बाधाएँ. International Journal of Agriculture Extension and Social Development, 7(5), 123–125.
6. कुमारी, आर., कुमारी, के., मिश्रा, वी., प्रियदर्शिनी, एस., कुमारी, आर., और रानी, एस. (2026). ग्रामीण महिलाओं में व्यवहारिक बदलावों पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रभाव. International Journal of Social Science and Humanities Research, 14(1), 39–42.
7. Ministry of Petroleum and Natural Gas- (2025). प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (प्रधानमंत्री उज्जवला योजनाः योजना के बारे में. भारत सरकार, पृ. 142
8. शर्मा, पी., और सिंह, आर. (2021). उत्तरी भारत की ग्रामीण महिलाओं में पारंपरिक खाना पकाने वाले ईंधनों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव. Journal of Rural Development Studies 18(2), 55–68.

9. Transforming India. (2025). PM Ujjwala Yojana: बेहतर जीवन. भारत सरकार, पृ. 77
10. World Health Organization- (2022). घरेलू वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य. World Health Organization- पृ. 89

***